DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

1 August, 2024

F&O सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के उपाय

संदर्भ: सुरक्षा और विनिमयमन बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI), जो पूंजी बाजारों का नियामक है, ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स भाग में सट्टा व्यापार को कम करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए है।

➢ डेरिवेटिव के प्रकार

- **डेरिवेटिव का अवलोकन:** वित्तीय अनुबंध स्टॉक, कमोडिटीज या मुद्राओं जैसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करते हैं। वहीं इंडेक्स डेरिवेटिव अंतर्निहित सूचकांकों से मूल्य प्राप्त करते हैं।
- **वायदा:** खरीदार को एक विशिष्ट तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने के लिए बाध्य करता है।
- **विकल्प:** किसी विशिष्ट तिथि पर किसी विशिष्ट मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति का व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं देता है।

➢ सेबी द्वारा प्रस्तावित उपाय

- **न्यूनतम अनुबंध आकार:** सूचकांक डेरिवेटिव (index derivatives) के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार को 5-10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15-20 लाख रुपये किया जाएगा, जिसे आगे बढ़ाकर 20-30 लाख रुपये किया जा सकता है।
- **विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह:** ब्रोकरों को ग्राहकों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- **स्थिति सीमाओं की इंट्राडे निगरानी:** सूचकांक व्युत्पन्न के लिए स्थिति सीमाओं की निगरानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) द्वारा इंट्राडे आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अल्पकालिक निर्धारण और लचीला पथ (glide path) होना चाहिए।
- **साप्ताहिक इंडेक्स उत्पादों का युक्तिसंगतकरण**: एकल बेंचमार्क इंडेक्स पर साप्ताहिक ऑप्शन अनुबंध प्रदान करें, न कि दैनिक समाप्तियों पर।
- **समाप्ति दिन पर कैलेंडर स्प्रेड लाभ की समाप्ति:** एक ही दिन समाप्त होने वाले अनुबंधों के लिए कैलेंडर स्प्रेड स्थितियों पर कोई मार्जिन लाभ नहीं होगा।
- **ऑप्शन स्ट्राइक की युक्तिसंगतकरण**: इंडेक्स मूल्य के निकट 4% तक समान स्ट्राइक प्राइस अंतराल, स्ट्राइक के दूर होने पर अंतराल बढ़ते हुए और अनुबंध लॉन्च पर अधिकतम 50 स्ट्राइक्स की पेशकश की गई।
- **अनुबंध समाप्ति के करीब मार्जिन में वृद्धि**: समाप्ति के एक दिन पहले अत्यधिक नुकसान मार्जिन (**ELM**) को 3% और समाप्ति के दिन 5% बढ़ाना है।

➢ उपायों का तर्क:

- **केंद्रीय बजट 2024-25:** वित्त मंत्री ने 1 अक्टूबर 2024 से प्रतिभूति के F&O पर सुरक्षा लेन-देन कर (**STT**) को दोगुना करने का प्रस्ताव किया है।
- **ट्रेडिंग हानियाँ:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में, **NSE** इंडेक्स डेरिवेटिव्स में 92.50 लाख व्यापारियों ने ₹51,689 करोड़ की हानियाँ उठाईं जबकि केवल 14.22 लाख (15%) ने शुद्ध लाभ कमाया।
- **बाजार की प्रतिक्रिया:** प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य डेरिवेटिव्स बाजार में खुदरा निवेशकों के बीच अति उत्साह को कम करना है।

Futures	Options
A buyer has to purchase the stocks at the time of delivery irrespective of its price (even if it's going low)	A buyer can forgo the decision of buying stocks if there is a drop or may not buy at all
Requires higher margin payment than options	Has lower margin payment as compared to futures
There is unlimited profit and risks are also high	There is limited loss potential and unlimited profit due to its flexibility to purchase stocks or not at the said date
Requires no upfront cost apart from commissions	There is a premium required to pay
The underlying position in futures is much more than options	Underlying position is lower than futures

संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

***संदर्भ** : हाल ही में कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने X पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर की एक भाषण का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कथित तौर पर हटाई गई सामग्री शामिल थी।*

- संसदीय विशेषाधिकार, संसद सदस्यों (एमपी) को संसदीय कार्य संचालित करने के लिए दिए गए अधिकार हैं।
- इनमें अदालती कार्यवाही का सामना किए बिना बहस के दौरान स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है।
- विशेषाधिकार का उल्लंघन की स्थिति में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है।
- प्रस्ताव को राज्य सभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तथा राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 203 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है।

➢ संसदीय प्रस्ताव

- **विषय** : एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के बारे में।
- **संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन:**
  - सांसदों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के अधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
  - इन अधिकारों की अवहेलना विशेषाधिकार का उल्लंघन है, जो संसदीय कानून द्वारा दंडनीय है।
  - किसी भी सदस्य द्वारा उल्लंघन के दोषी के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना शामिल है।
- **अध्यक्ष/राज्यसभा (आरएस) सभापति की भूमिका:**
  - यह विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए जांच के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करता है।
  - यह प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या उसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।
  - यदि यह सहमति दे तो सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **विशेषाधिकार संबंधी नियम:**
  - यह लोक सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 के नियम संख्या 222 तथा राज्य सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 के नियम 187 द्वारा शासित है।
  - सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं।

➢ **संसदीय विशेषाधिकार:**

- **परिभाषा** : संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों के लिए विशेष अधिकार, उन्मुक्ति और छूट प्रदान की गई है।
- **दायरा** :
  - इसमें संसदीय कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग भी शामिल हैं, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्री।
  - इसमें राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अलग विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 105 संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार को निर्दिष्ट करता है।
  - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, संसदीय सत्र के दौरान तथा सत्र से पहले और बाद में चालीस दिनों तक गिरफ्तारी और नजरबंदी से उन्मुक्ति प्रदान करती है।
- **संहिताकरण** : संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को सम्पूर्ण रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।

➢ **विशेषाधिकार समिति**

- विशेषाधिकार समिति में लोक सभा के 15 सदस्य और राज्य सभा के 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
- राज्य सभा में उपसभापति समिति का नेतृत्व करते हैं।
- समिति विशेषाधिकार हनन से जुड़े प्रश्नों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें करती है।
- यदि समिति के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है तो रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- रिपोर्ट पर सदन द्वारा विचार किया जाता है और इसके द्वारा दिए गए संशोधन विचार किया जाता है।
- विशेषाधिकार प्रस्ताव में किसी विशिष्ट, हालिया मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
- अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति इस प्रस्ताव पर सीधे विचार कर सकते हैं या उसे समिति को भेज सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून

संदर्भ: *उत्तर प्रदेश अनधिकृत धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021, जो "अनधिकृत" तरीकों से धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है।*

➢ **उत्तर प्रदेश सरकार ने यह संशोधन क्यों पेश किया है?**

- संशोधन का उद्देश्य कमजोर समूहों, जैसे कि नाबालिगों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बेहतर सुरक्षा करना है।
- यह ऐसे चिंता को संबोधित करता है जो अधिनियम के तहत मौजूदा दंड धार्मिक रूपांतरण और सामूहिक रूपांतरण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त हैं तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 4 से संबंधित मुद्दों को भी हल करना है, जो पहले अनधिकृत धर्मांतरण के लिए FIR दर्ज करने की पात्रता को सीमित करता था।

➢ **संशोधन में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?**

- **विस्तारित एफआईआर फाइलिंग:**
  - यह संशोधन "किसी भी व्यक्ति" को अधिनियम के तहत उल्लंघनों के लिए FIR दर्ज करने की अनुमति देता है, न कि केवल "किसी भी पीड़ित व्यक्ति" को जैसा पहले कहा गया था।
  - नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत, व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो।
- **सख्त ज़मानत शर्तें:**
  - इस संशोधन में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के समान कठोर जमानत शर्तें शामिल की गई हैं।
  - आरोपी व्यक्तियों को जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब सरकारी अभियोजक को इसका विरोध करने की अनुमति दी जाए और अदालत को यह विश्वास हो जाए कि जमानत पर रहते हुए वे दोषी नहीं हैं और उसे कोई खतरा नहीं है।

➢ **बढ़ी हुई सज़ा:**

- **संशोधन से धारा 5 के अंतर्गत दंड में वृद्धि:**
  - मूल अपराध के लिए 3-10 वर्ष का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना है।
  - यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो तो 5-14 वर्ष का कारावास और कम से कम 1,00,000 रुपये का जुर्माना है।
  - सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए 7-14 वर्ष का कारावास और कम से कम 1,00,000 रुपये का जुर्माना है।
- **अपराधों की दो नई श्रेणियां शुरू की गई हैं:**
  - गैरकानूनी धर्मांतरण से संबंधित विदेशी या अवैध स्रोतों से धन प्राप्त करना, जिसके लिए 7-14 वर्ष का कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  - भय पैदा करना, हमला करना, या तस्करी करना, जिसके लिए 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
  - विवाह के माध्यम से अवैध धर्म परिवर्तन, जिसके लिए वर्तमान में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, को बढ़ाकर न्यूनतम 20 वर्ष कारावास किया जा सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

1 August, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

'तरंग शक्ति 2024'

भारत अगले महीने की 6 तारीख से तमिलनाडु के सुलार में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति 2024' आयोजित करेगा, जिसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे और इनमें से दस देश लड़ाकू विमान के साथ भाग लेंगे।

तरंग शक्ति 2024 के बारे में: -

- तरंग शक्ति 2024 अगस्त और सितंबर 2024 में भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा आयोजित दो चरणों वाला सैन्य अभ्यास है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना, भारत के रक्षा उद्योग को प्रदर्शित करना और भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी विश्वास का निर्माण करना है।
- इस अभ्यास में विभिन्न प्रकार के विमान शामिल होंगे, जिनमें LCA तेजस जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म और राफेल एवं सुखोई लड़ाकू विमान जैसी उन्नत प्रणालियाँ शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर सहित 10 देश अपने विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे और 18 देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे।
- भारत के लड़ाकू विमान, जिनमें तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर, एमआईजी 29 विमान आदि इस अभ्यास में भाग लेंगे।
- इस अभ्यास में प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों, स्टार्टअप्स, डीआरडीओ, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और विमानन उद्योग की एक रक्षा औद्योगिक प्रदर्शनी भी शामिल होगी।
- दूसरा चरण 1-14 सितंबर तक जोधपुर में होगा।

सीन नदी

एथलीटों ने हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में सीन नदी में महिलाओं की व्यक्तिगत ट्रायथलॉन (Individual triathlon) के तैराकी घटक की शुरुआत की गई।

सीन नदी के बारे में:

- सीन नदी फ्रांस में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है, जो अपने ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है।
- यह लॉयर के बाद फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- यह नदी बरगंडी क्षेत्र में, डिजॉन के पास उत्पन्न होती है।
- यह अटलांटिक महासागर की एक शाखा, इंग्लिश चैनल में गिरती है।
- इस नदी के दाहिने किनारे पर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मार्ने नदी मिलती है।
- यह प्रारंभिक मध्य युग से ही पेरिस के लिए महत्वपूर्ण रही है।
- नदी बेसिन का अधिकांश भाग पारगम्य चट्टानों से बना है, जो पानी को अवशोषित करते हैं और नदी की बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं।

महतारी वंदन योजना

आज 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महतारी वंदन योजना की छठी किस्त जारी करेंगे और महतारी वंदन ऐप लॉन्च करेंगे। यह ऐप लाभार्थियों के मासिक भुगतान और बैंक विवरण प्रदान करेगा।

महतारी वंदन योजना के बारे में:

- महतारी वंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई एक योजना है।
- इस योजना का लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, परिवार में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करना है।
- यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना छत्तीसगढ़ की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करती है, जिनकी आयु 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है।
- विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं

कृष्णराज सागर जलाशय

हाल ही में, कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अधिकारियों ने कर्नाटक में कृष्णराज सागर (केआरएस) और काबिनी बांधों से जल के बहाव का स्तर बढ़ा दिया है।

कृष्णराज सागर जलाशय/बांध के बारे में:

- कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध कर्नाटक के मांड्या जिले में एक गुरुत्वीय बांध है।
- यह कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों, हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम के नीचे स्थित है।
- केआरएस बांध का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और यह मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ महाराज के शासनकाल के दौरान 1931 में पूरा हुआ।
- बांध का डिज़ाइन प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर एम. विश्वेश्वरैया (15 सितंबर को उनका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है) द्वारा बनाया गया था।
- यह सीमेंट के बजाय सुरकी मोर्टार से बना है क्योंकि उस समय भारत में सीमेंट का निर्माण नहीं होता था।
- बांध 2,621 मीटर (8,600 फीट) लंबा, 40 मीटर (130 फीट) ऊंचा है और इसमें 177 लोहे के जलद्वार हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	कावेरी नदी - ▪ कावेरी नदी दक्षिण भारत में एक पवित्र नदी मानी जाती है और इसे अक्सर 'दक्षिण भारत की गंगा' कहा जाता है। ▪ यह नदी दक्षिण-पश्चिमी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ▪ इसका बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों में फैला हुआ है। ▪ कावेरी की प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियों में हरंगी, हेमवती, शिमशा और अर्कावती नदियाँ शामिल हैं।
समाचार में स्थान **स्विट्जरलैंड**	*स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है।* राजधानी: बर्न **स्थान:** स्विट्जरलैंड एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जो मध्य यूरोप में स्थित है। **राजनीतिक सीमाएँ:** स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया और लिकटेंस्टीन (पूर्व), फ्रांस (पश्चिम), जर्मनी (उत्तर) और इटली (दक्षिण) के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। **भौतिक विशेषताएँ:** ▪ स्विट्जरलैंड का सबसे ऊँचा स्थान डुफोरस्पिट्ज है, जो आल्प्स में मोंटे रोजा मासिफ का हिस्सा है। ▪ स्विट्जरलैंड की प्रमुख झीलें लेक जिनेवा (लेक लेमन), लेक कॉन्स्टेंस (बोडेंसी) और लेक ज्यूरिख हैं। ▪ स्विट्जरलैंड की प्रमुख नदियाँ राइन, रोन, आरे और टिसिनो हैं। **सदस्यता:** ▪ स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) का सदस्य है और शेंगेन क्षेत्र में भाग लेता है, लेकिन यूरोपीय संघ (ईयू) का सदस्य नहीं है। **स्विस राष्ट्रीय दिवस:** ▪ 1 अगस्त को, स्विट्जरलैंड 1291 के संघीय चार्टर पर हस्ताक्ष किया तथा जिसमें उरी, श्विज़ और अन्टरवाल्डेन के इलाकों ने हमला होने पर एक-दूसरे की मदद करने का वचन दिया था।

POINTS TO PONDER

- इंडिया@100: एनविज़निंग टुमॉरोज़ इकनोमिक पावरहाउस' नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसका हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में विमोचन किया? – **प्रो. के. वी. सुब्रमण्यन**
- हाल ही में नागेंद्र नाथ सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद इस्पात मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? – **चंद्र लाल दास**
- हाल ही में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत सप्लाई चेन काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? – **भारत**
- हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? – **हरिभाऊ किसनराव बागड़े (महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता)**
- हाल ही में मनोज सोनी के पद से इस्तीफा देने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? – **प्रीति सूदन (पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव)**